मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो ।

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 47 | मई 1992 | 50 पैसे

नई राह जरूरी है ।

ओसवाल स्टील

बर्द्धमान स्पिनिंग लुधियाना के यहाँ 24 सैक्टर स्थित मिनी स्टील प्लान्ट में इस समय 6-7 सौ मजदूरों का काम है। रोलिंग और मेन्टेनैन्स के पौने दो सौ मजदूर ही करीब साल-भर से डियूटी पर हैं। जून 91 से स्टील मैल्टिंग शाप के 190 परमानेन्ट वरकर, दस साल से काम कर रहे 24 कैजुअल वरकर और बिना किसी रिकार्ड वाले 250 ठेकेदारी वरकर फैक्ट्री गेट के बाहर कर दिये गये हैं।

तीन-चार महीने की तालाबन्दी, जिसे पूँजीवादी पक्ष हड़ताल करार देता रहा है, वह कई साल से ओसवाल स्टील मैनेजमेन्ट का मजदूरों के खिलाफ एक घातक हथियार रहा है। जून 91 में नई लगी एल आर एफ फरनेस के मामले में भी मैनेजमेंट ने अपने आजमाये हुये औजार का ही इस्तेमाल किया। और बार-बार नाकारा साबित हुये पूँजीवादी कानूनी अखाड़े में मजदूर फिर फँसे/फांसे दिये गये जबकि :—

1, बिना रिकार्ड वाले, 22-25 रूपये रोजनदारी पर रखे 250 मजदूरों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी में सबूत हासिल हुये लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने का उदाहरण ओसवाल स्टील मजदूरों के सामने था।

2. 1986 में निकाला गया एक मजदूर जून 90 में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का फैसला लाया। मैनेजमेन्ट ने स्टील प्लान्ट के इस क्रेन आपरेटर को यहां डियूटी पर लेने से इनकार कर दिया और लुधियाना में स्पिनिंग मिल में डियूटी ज्वाइन करने को कहा। इस प्रकार मैनेजमेन्ट ने पूँजीवादी कानून और यहाँ उसके सुप्रीम कोर्ट की हकीकत की एक और झलक ओसवाल स्टील मजदूरों को प्रत्यक्ष तौर पर दिखा दी थी। मुखर क्रेन आपरेटर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर थामे करीब दो साल से लेबर डिपार्टमेन्ट और वकीलों के चक्कर काट रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के कागजी आर्डर को डेढ साल और परमानेन्ट मजदूरों को गेट बाहर हुये 9 महीनों से ऊपर हो गये तब बदहवासी में कदम उठाया गया। 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट वाले मजदूर ने आमरण अनशन का नोटिस डी सी-एस पी आदि को दिया और 20 मार्च को अनशन शुरू कर दिया। बाहर किये हुये 190 परमानेन्ट मजदूरों में से 60-70 ही एकत्र हो पाये। रोलिंग और मेन्टेनैन्स के डियूटी कर रहे मजदूर दूरी बनाये रहे—एक तो वे अपने बाहर किये गये साथियों का हाल देख रहे थे और फिर छँटनी उनके सामने मुंह बाये खड़ी थी क्योंकि रोलिंग में मैनेजमेन्ट ने कम्प्यूटर युक्त आटोमेटिक लिफ्टिंग सिस्टम लागु कर दिया था जिसकी वजह से 44 की जगह 11 मजदूर पर्याप्त होंगे। वैसे भी, अनशन का फैसला लेने वालों ने डियूटी कर रहे मजदूरों से तालमेल के लिये कोई खास प्रयास नहीं किया।

24 मार्च को भूखहड़ताली मजदूर को पुलिस उठा कर अस्पताल ले गई। इस बारे में सोचा तक नहीं गया था। खैर, दूसरा मजदूर अनशन पर बैठा जिसे 29 मार्च को पुलिस उठा ले गई। उसके बाद तीसरे-चौथे-पाँचवें-छठे भूखहड़ताली मजदूर के साथ भी पुलिस ने ऐसा ही किया। और 14 अप्रैल को फैक्ट्री गेट से 50 गज पर लगे तम्बू को 200 गज दूर ले जाने का पुलिस ने हुकुम दिया।

पुलिस की धमकियाँ बढ रही थी। गेट से उठा दिये जाने पर भी मजदूर अनशन जारी रखे थे। पर इस रास्ते से कोई नतीजा नहीं निकलता देख कर भूखहड़ताल की राह पर चले ओसवाल स्टील के मजदूरों ने आपस में सलाह-मशविरा करके, मैनेजमेन्ट अथवा अन्य किसी से बिना किसी समझौते के 17 अप्रैल को अनशन खत्म कर दिया।

आज मजदूरों के न तो पूँजीवादी कानून कोई खास काम आते हैं और न ही कोई मसीहा-महाबलि महाज्ञानी कोई विशेष काम का रहा है। बदहवासी में उठाये कदम नुक्सान ही पहुँचाते हैं। आज की हालात में मजदूर पक्ष की ताकत बढाने के लिये नई राह की खोज जरूरी है। संघर्ष और संगठन के नये रूपों पर विचार करना जरूरी हो गया है।

के जी खोसला कम्प्रेसर

दिल्ली-फरीदाबाद बार्डर स्थित इस प्रमुख कम्प्रेसर निर्माता फैक्ट्री में 5 सितम्बर से तालाबन्दी जारी है। यहाँ काम कर रहे 250 कैजुअल और ठेकेदारी वरकरों का क्या हुआ ? ऐसे सवाल ही आजकल आमतौर पर अजूबे-बचकाने माने जाते हैं। खैर, यहा हम दो हजार परमानेन्ट मजदूरों के अनुभव पर एक नजर डालेंगे।

तीन साल वाले एग्रीमेन्ट के लिये जून 91 में मैनेजमेन्ट को डिमान्ड नोटिस दिया गया। इस पर कम्पनी की हालत खराब है, वरकर ज्यादा हैं की रट मैनेजमेन्ट ने लगाई। बीस परसैन्ट दिये जा रहे बोनस की जगह 8 पाइन्ट 33 की बात की। 326 परमानेन्ट मजदूरों को छँटनी का नोटिस लगाया। क्लोजर की धमकी दी। इस सिलसिले में अगस्त 91 का वेतन मजदूरों को नहीं दिया और 5 सितम्बर को लाकआउट कर दिया। तालाबन्दी करके नवम्बर में (दिवाली पर) बोनस की बात ही मैनेजमेन्ट ने आई-गई कर दी।

के जी खोसला कम्प्रेसर मैनेजमेन्ट द्वारा की गई तालाबन्दी के खिलाफ कागजी घोड़े थोक में दौड़ाये गये। दिल्ली में हरियाणा भवन पर प्रदर्शन। दिल्ली में चेयरमैन की कोठी पर धरने। दिल्ली में गिरफ्तारियाँ दी गई। फरीदाबाद में लेबर डिपार्टमेन्ट-डी सी-एम पी-मन्त्री के पास कई बार जलूस। यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परम्परागत कदम के जी खोसला मजदूरों ने उठाया है। रिजल्ट है वही ढाक के तीन पात।

आठ महीनों से जारी तालाबन्दी के दौरान जनता दल के एक शातिर के हर हुकुम का इन मजदूरों ने आँख मूँद कर पालन किया है। इस दौरान के जी खोसला मजदूरों को कई ठोकरें लगी हैं। पर आँख खोल कर दो और दो चार जोड़ने की वजाय यह मजदूर सोलह दूनी आठ की रट ही लगाये हैं। जनता दल साहब के आदेशों का इन्तजार जारी है .....

पूंजीवादी पक्ष के खिलाफ मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ाने वाले कदम उठा कर ही पराजयों के सिलसिले को मजदूर तोड़ सकेंगे। पूँजीवादी गुटों की हिस्सा-पत्ती के लिये छीना-झपटी में किसी गुट के औजार बन जाना मजदूरों की बरबादी की राह है। कांग्रेस-भाजपा-जनतादल-नकली कम्युनिस्ट एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। फैक्ट्रियों में मजदूरों पर मैनेजमेन्टों के हमलों के वक्त इनके छुटभैय्यों, इन्टकऐटक-सीटू-बी एम एस-एच एम एस के करमों के रूप में पूँजीवादी, सरगनों की हकीकत बार-बार सामने आती है। लेकिन संगठन और संघर्ष के पुराने रूप मजदूरों को बार-बार पूँजीवादी दलदल में फँसाते हैं।

पूँजीवादी हमले तालाबन्दी के रूप में हों चाहे अन्य किसी ढंग से, इनसे मुकाबले के लिये नई राह की तलाश मजदूरों के लिये जरूरी हो गई है।

जर्मनी में हलचल

पूँजीवादी व्यवस्था के संकट के असर जर्मनी जैसे तथा कथित खुशहाल टापूओं में भी साफ-साफ दिखने लगे हैं। विद्यमान से बेरूखी-अरूचि, महँगाई और बेरोजगारी की तेज होती आँच के रूप में मौजूदा व्यवस्था का गहराता संकट जर्मनी में स्वयं को नई धाराओं में अभिव्यक्त करने को अग्रसर हुआ है।

स्थापित पूँजीवादी धाराओं के खिलाफ कुछ समय पहले ग्रीन पोलिटिक्स सामने आई। पूँजीवादी व्यवस्था के मानवद्रोही लक्षणों, विशेषकर इसमें पर्यावरण प्रदूषण/विनाश ने जर्मनी में ग्रीन पोलिटिक्स को जन्म दिया। भावना से ओत-प्रोत यह धारा तेजी से यूरोप-अमरीका व्यापी बन गई। लेकिन कई अत्यधिक महत्व के प्रश्नों को सामने लाने के बावजूद शीघ्र ही ग्रीन पोलिटिक्स उदारवादी पूँजीवादी अखाड़े के एक और लाइटवेट पहलवान में परिवर्तित हो गई। फिर भी, ग्रीन्स द्वारा उठाये सवाल आने वाले दिनों में और तीखेपन के साथ उठेंगे।

महँगाई से परेशान सफाई वरकरों और डाक विभाग के वरकरों ने 24 अप्रैल से दस प्रतिशत वेतन बृद्धि के लिये हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रान्सपोर्ट वरकर इस हड़ताल में शामिल हो गये हैं। इस प्रकार एक लाख सत्तर हजार मजदूर इस समय जर्मनी में हड़ताल पर हैं। गया 1974 वाला दौर जब हड़ताल को तीन दिन ही हुये थे कि जर्मनी सरकार ने मजदूरों की माँगें मान कर हड़ताल समाप्त करवा दी थी। अब हाथ तंग होने, बेकाबू होते बजट घाटे की वजह से जर्मनी सरकार वैसा करने में असमर्थ है। आने वाले दिनों में जर्मनी में मजदूरों का असन्तोष बढेगा।

महँगाई- बेरोजगारी - आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पिछले दिनों जर्मनी के दो प्रदेशों के चुनावों में हिटलरी धारा की शक्ति में चौंकाने वाली वृद्धि के रूप में भी हुई। आने वाले दिनों में जर्मनी में हिटलरी-फासिस्ट धारा के जोर पकड़ने की आशंका है।

समस्या की जड़ जर्मन एकीकरण नहीं है। न ही वृहद्तर जर्मनी/शुद्ध जर्मनी समस्या का समाधान है। लक्षणों पर फोकस वाली हड़तालें हों चाहे मानव-प्रकृति के रिश्तों के गम्भीर प्रश्न वाले आन्दोलन हों, सामाजिक प्रक्रिया की छिछली समझ इन्हें हाशियों पर धकेल दिये जाने की सम्भावना बढाती है। ऐसी परिस्थिति में हिटलरी-फासिस्ट धारा का शक्तिशाली बनना लाजिमी है क्योंकि यह टिकी ही सामाजिक प्रक्रिया की छिछली समझ पर होती है।

समस्या जर्मन या भारतीय नहीं है। समस्या है पूंजीवादी व्यवस्था का गहराता व लाइलाज संकट। इसकी वजह से स्थापित सरकारें/संस्थायें तो अधिकाधिक मानवद्रोही हो ही रही हैं, इनसे भी इक्कीस हिटलरी अथवा खुमैनीनुमा धारायें भी शक्तिशाली बन रही हैं। इनके बिकल्प के प्रयासों के थोथे परिणामों से बचने के लिये सामाजिक प्रक्रिया की गहराई मे जाँच-परख आवश्यक है।

संपर्क — मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

क्लच आटो

12/4 मथुरा रोड स्थित इस फैक्ट्री से 4 अप्रैल को 250 कैजुअल वरकर निकाल दिये गये। आठ-दस साल से लगातार काम कर रहे इन मजदूरों से अत्यधिक काम लिया जाता रहा है। एक मशीन पर काम खत्म होने पर दूसरी पर इन्हें लगाया जाता रहा हैं। इन्हें सरकारी न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया। ई एस आई तक इन मजदूरों की नहीं काटी गई। महीने में तीसों दिन काम और पानी-बीड़ी पीने जाने पर आधे दिन की एबसेन्ट यह मजदूर भुगतते रहे हैं। और अब यूनिवर्सल इंजिनियरिंग आदि फैक्ट्रियों की ही तरह क्लच आटो के कैजुअल वरकरों को बलि के बकरे बनाने के हालात उभर रहे हैं।

जुलाई 91 में क्लच आटो में तीन सालाना एग्रीमेन्ट हुआ। जैसा कि ढर्रा है, एग्रीमेन्ट 500 परमानेन्ट वरकरों के लिये ही था, 250 कैजुअल वरकरों का इसमें जिक्र तक नहीं था। परमानेन्ट वरकरों के लिये 150 रूपये की बढोतरी भी चालू ढर्रे के मुताबिक वर्क लोड में वृद्धि लिये थी। लेकिन मैनेजमेन्ट जितना प्रोडक्शन बढाना चाहती थी वह नही हो पाया। इस पर मैनेजमेन्ट ने 150 रूपये, जूते आदि वाली एग्रीमेन्ट लागू नहीं की। इन हालात में परमानेन्ट मजदूरों का यूनियन नेताओं के खिलाफ असन्तोष बढ़ना स्वाभाविक था।

लगता है कि एच एम एस से जुड़े यूनियन नेताओं ने ऐसे में कैजुअल मजदूरों को परमानेन्ट करने की माँग उछाल दी। 4 अप्रैल को मैनेजमेन्ट द्वारा 250 कैजुअल मजदूरों को सड़क पर धकेल दिया जाना इस सिलसिले की एक कड़ी है। 27 अप्रैल को 12 मुबर परमानेन्ट मजदूरों को सस्पैन्ड किया जाना खींचा-तान की अगली कड़ी है। फैक्ट्री में नोरमल प्रोडक्शन हो रहा है।

एक साथ निकाले गये और गुस्से से भरे क्लच आटो के 250 कैजुअल वरकर संगठित हुये हैं। इस पर मैनेजमेन्ट इन मजदूरों के खिलाफ अदालत से 50 गज वाला स्टे ले आई है। 26 अप्रैल को मैनेजमेन्ट के गुन्डों ने इन मजदूरों को धमकियाँ दी और मुखर कैजुअल वरकरों के घरों पर जा कर परिवारों तक को गुन्डे धमका रहे हैं।

एक दिक्कत यह हैं कि मसीहा बने लोगों के आदेशों पर कैजुअल वरकर लेवर डिपार्टमेन्ट आदि में कागजी घोड़ों पर आस लगाये हैं। तारीखों के चक्कर में महीना-क खराब हो चुका है। समय की और बरबादी क्लच आटो के निकाले हुये कैजुअल वरकरों की ताकत को बिखेर देगी। इन मजदूरों को ऐसे कदमों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये जो इनकी ताकत को बढ़ायेंगे।

यह याद रखने की जरूरत है कि 1983-84 में 6 सैक्टर से मथुरा रोड शिफ्ट करने के वक्त क्लच आटो मैनेजमेन्ट ने सीटू की मिलीभगत से सैकड़ों परमानेन्ट मजदूर निकाल दिये थे। मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में कुछ साल इन्टक का ड्रामा चला और अब एच एम एस का नाटक जारी है। केल्विनेटर थामसन प्रेस-के जी खोसला कम्प्रेसर के हाल के घटनाक्रम पर क्लच आटो के निकाले हुये कैजुअल मजदूरों को तो तत्काल गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है ही, परमानेन्ट मजदूरों के लिये भी इनको अनदेखा करना घातक होगा। और हां क्लच आटो के परमानेन्ट मजदूरों को यूनिवर्सल इंजिनियरिंग के अनुभव से सबक लेना चाहिये। यूनिवर्सल में तीन सालाना एग्रीमेन्ट में अपने क्षुद्र हितों के लिये परमानेन्ट मजदूरों ने कैजुअल वरकरों को बलि के बकरे बनाया था। और फिर मैनेजमेन्ट ने उन परमानेन्ट मजदूरों को ही धार पर धर दिया।

किसी के आदेशों का मुंह ताकने की बजाय आम मजदूरों की पहल-कदमी मजदूर पक्ष की मजबूती के लिये जरूरी है। क्लच आटो के निकाले हुये कैजुअल वरकर एक कदम के तौर पर हर रोज फैक्ट्री से सराय तक जलूस निकालें।

अल्फा टोयो

9 एच सैक्टर 6 स्थित अल्फा टोयो में आटो पार्टस बनते हैं। इस फैक्ट्री में 120 परमानेन्ट, 40 कैजुअल और 20 ठेकेदारी वरकर हैं तथा 100 का स्टाफ है। 9 अप्रैल से अल्फा टोयो में तालाबन्दी है।

5 अक्टूबर 91 को तीन सालाना एग्रीमेन्ट हुआ। इसमें मजदूरों को आल इंडिया डी ए देने की बात भी थी जिसे 6 महीने बाद लागू किया जाना था। मार्च 92 में इस पर अमल के समय मजदूरों को सरकारी कागज से पता चला कि मैनेजमेन्ट ने धोखा धड़ी की हैं। तब डी ए के सवाल पर मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच खींचा-तान शुरू हुई।

सरकारी कानून के मुताबिक जिस फैक्ट्री में एक हजार से कम मजदूर काम करते हैं वहाँ नये महीने की सात तारीख से पहले बीते महीने का वेतन मजदूरों को दिया जाना चाहिये। अल्फा टोयो मैनेजमेट ने 7 अप्रैल तक मार्च माह का वेतन मजदूरों को नहीं दिया। इस पर 8 अप्रैल को मजदूरों ने तैयार माल को फैक्ट्री से बाहर ले जाने पर रोक लगाई। पुलिस की मदद से 8 अप्रैल को ही मैनेजमेन्ट तैयार माल फैक्ट्री से बाहर ले गई।

8 अप्रैल की रात पाली के मजदूरों को फैक्ट्री में चाय देने में आई दिक्कत के बहाने मैनजमेन्ट उन्हें 9 अप्रैल को सुबह-सबेरे चाय पिलाने बाहर ले गई.....और फैक्ट्री में तालाबन्दी कर दी। मैनेजमेन्ट कह रही है कि मजदूरों ने हड़ताल की हैं।

मैनेजमेन्ट की कार्रवाई के खिलाफ अल्फा टोयो के मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर धरना शुरू कर दिया। 11 अप्रैल रात को गुन्डों ने धरने पर बैठे मजदूरों को धमकियाँ दी। 17 अप्रैल को पुलिस की मदद से मैनेजमेन्ट फैक्ट्री से कच्चा माल और डाइयाँ निकाल कर ले गई। इसके बिरोध में 18 को मजदूरों का जलूस डी सी एस पी दफ्तरों पर गया।

21 अप्रैल को मैनेजमेन्ट फैक्ट्री गेट से 200 गज दूर वाला स्टे ले आई। अब मजदूर मथुरा रोड पर धरने पर बैठे हैं। उकसावे की अन्य हरकतों के साथ-साथ लेडीज स्टाफ के जरिये मैनेजमेन्ट झगड़ा कराने की कोशिश कर रही है।

अल्फा टोयो के मजदूरों ने जगह-जगह कागजी घोड़े दौड़ाये है। पूंजीवादी कानून की अखाड़ेबाजी की जरूरतें भी यह मजदूर पूरी कर रहे हैं। धरने पर यह बैठे ही है।

इन मजदूरों को के जी खोसला केल्विनेटर, प्यालो, थामसन प्रेस, स्टेरीवेयर, सपना-सोमाग टैक्सटाइल्स के मजदूरों के कड़वे अनुभवों से सबक लेने चाहियें। मैनेजमैंटों के हमलों के खिलाफ मजदूरों के परम्परागत बिरोध के तरीके कारगर साबित नही हो रहे। आमतौर पर पुराना ढँग मजदूरों को दलदल में धँसाता हैं। ऐसे में मजदूर पक्ष की ताकत बढाने के लिये अन्य कदमों पर विचार करना जरूरी है। इस सम्बन्ध में अल्फा टोयो मजदूरों को हर रोज सुबह पौने आठ से साढे आठ बजे तक मथुरा रोड पर बल्लबगढ व वाई एम सी ए तक जलूसों पर विचार करना चाहिये। हर रोज एक घन्टे का जलूस एक तो अल्फा टोयो मजदूरों को बिखरने से रोकने में सहायक होगा और दूसरे यह पूंजीवादी पक्ष को बैठ कर तमाशा देखने की जगह हरकत में लायेगा। पाँच सात दिन लगातार स्वयं जलूस निकालने के बाद अल्फा टोयो मजदूर अपने परिवारों के सदस्यों तथा अन्य फेक्ट्रियों के मजदूरों को इन जलूसों में शामिल करके मजदूर पक्ष की ताकत बढाने में सफल होंगे। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

भिलाई

पिछले बीस महीनों से भिलाई-उरला-टेडेसरा-कुम्हारी इन्डस्ट्रीयल एरिया के मजदूर वेतन वृद्धि-स्थाई काम पर परमानेन्ट वरकर रखने-संगठन बनाने के हक-छँटनी किये गये मजदूरों की बहाली आदि 9-सूत्री मांगों के लिये आन्दोलनरत हैं। इन बीस महीनों में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री-मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं, सबके दरवाजे खटखटाये गये हैं। आवेदन-निवेदन-धरना - भूखहड़ताल-मीटिंग-जलूस आदि सभी परम्परागत तरीके आजमाये जा चुके हैं। इनसे माँगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि, मजदूरों की छँटनी-धारा 144-मजदूरों पर घातक हमले-झूठे केसों में फँसाकर मजदूरों को जेल में डालना रोजमर्रा की घटना बन चुकी हैं। 25 हजार मजदूर परिवारों को भूखा मार कर झुकाने के लिये पूंजीवादी पक्ष का हमला जारी है। मैनेजमेन्टों-गुण्डों पुलिस-प्रशासन-सरकार का गठबन्धन, पूंजीवादी पक्ष भिलाई क्षेत्र के आन्दोलनरत मजदूरों पर हावी है।

शंकर गुहा नियोगी की सितम्बर 91 में हत्या के बाद के सात महीनों में मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आया है, हालात और खराब हुये हैं। 24 जनवरी 92 को छत्तीसगढ डिस्टिलरी मैनेजमेन्ट ने बड़ी मात्रा में पुलिस एकत्र करके 800 मजदूर एकमुश्त नौकरी से निकाल दिये।

इस बीच क्षेत्र के प्रमुख सीटू लीडर द्वारा एक मैनेजमेन्ट की नौकरी ज्वाइन करना और सिम्पलेक्स में हड़ताल तोडने के लिये लेबर सप्लायर बनी एटक को इन मजदूरों ने अपनी आँखों से देखा है। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद भिलाई क्षेत्र में बने बनाये मँच से जनता दल लीडरों की दहाडें इन मजदूरों के लिये भी अब बीते जमाने की चीजें बन गई है।

ऐसे में भिलाई क्षेत्र के आन्दोलनरत मजदूरों की मजबूती के लिये 5 लाख मेहनतकशों को एकत्र करके भिलाई ठप्प करने की घोषणा की गई है। इस पर अमल की तैयारी के सिलसिले में मार्च के अन्त से टोलियाँ प्रचार अभियान में जुटी हैं। भिलाई ठप्प करने की तारीखें निश्चित नहीं की गई हैं।

हमारे विचार से काफी समय से चौराहे पर पहुचे भिलाई क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन द्वारा दिशा के प्रश्न को अब और लटकाया नहीं जा सकता। वर्तमान में मजदूर पक्ष क्या है इस बारे में नये सिरे से विचार करना जरूरी है। हमारे विचार से राष्ट्रीयता की राह दलदल की राह है। जाति-धर्म-राष्ट्रीयता-देश आदि की विरासत में मिली बेड़ियों को तोड़ते हुये दुनियाँ के मजदूरों की एकता की राह पर बढना ही आज मजदूर पक्ष के निर्माण की राह है।

'एक मजदूर के अनुभव' सीरीज को इस अंक में जारी नहीं रख पाने का हमें खेद है। अगले अंक से इसे नियमित करने की हम कुछ और कोशिश करेंगे।

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने क काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, सगठन और सघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लियेबेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित